हम जैसा सोचते है वैसे ही बन जाते है।
– अज्ञात

दुनिया ने राहत की सांस ली

अमेरिकी सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच पहले चरण की ट्रेड डील पर सहमति गुरुवार को ही बन गई थी। इसके तहत 160 अरब डॉलर के चाइनीज इंपोर्ट पर 15 दिसंबर से प्रस्तावित अमेरिकी आयात शुल्क टल जाएगा।

आशा नेगी

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते की एकतरफा खबर से दुनिया ने राहत की सांस ली है। शेयर बाजारों ने इसका उछाल के साथ स्वागत किया और न सिर्फ अमेरिकी बल्कि भारत समेत कई एशियाई बाजारों में भी इस खबर से तेजी देखी जा रही है। चीन की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो बाजार के उत्साह को देखते हुए थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन अमेरिकी मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, केवल इसे आधिकारिक रूप देना बाकी है। अमेरिकी सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच पहले चरण की ट्रेड डील पर सहमति गुरुवार को ही बन गई थी। इसके तहत 160 अरब डॉलर के चाइनीज इंपोर्ट पर 15 दिसंबर से प्रस्तावित अमेरिकी आयात शुल्क टल जाएगा। जिन उत्पादों पर यह लगना था उनमें जूते, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने भी शामिल थे। चीन से आने वाले सामान पर पहले से लग रहे आयात शुल्क को भी घटाकर आधे पर ला दिया जाएगा।

चीन अगले साल अमेरिका से 50 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद और अन्य वस्तुएं खरीदने पर सहमत हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच वार्ता का यह दौर अक्टूबर से ही जारी था। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि इस वर्ष के अंत तक पहले चरण की डील हो सकती है। हालांकि, बीच–बीच में ट्रंप कुछ विरोधाभासी बयान भी दे देते थे जिससे आशंकाएं बढ़ जाती थीं। गनीमत है कि ट्रंप ने हालात की गंभीरता को समझा है। इधर कुछ समय से विश्व अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन के जो लक्षण देखे जा रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह अमेरिका–चीन ट्रेड वॉर को माना जा रहा है, जिसका दोष सीधे–सीधे ट्रंप पर जाता है। आईएमएफ का अनुमान है कि आयात कर को हथियार बनाकर लड़ी जा रही इस लड़ाई के चलते अमेरिका की ग्रोथ में 0.6 प्रतिशत और चीन की ग्रोथ में 2 प्रतिशत की कमी आई है।

ट्रेड वॉर के चलते चीन ने अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदना बंद कर दिया था। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक साल में अमेरिकी फार्म एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से घटकर 7 अरब डॉलर रह गया है। पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों के मुताबिक चीनी सामानों के इंपोर्ट पर अमेरिकी कंपनियां अपनी सरकार को हर महीने 5 अरब डॉलर का आयात शुल्क चुका रही हैं। आयात शुल्क में 50 प्रतिशत कमी से इन कंपनियों को हर महीने 2.5 अरब डॉलर की बचत होगी।

बहरहाल, दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर खत्म होना भारत के लिए भी पॉजिटिव होगा। अनिश्चितता खत्म होने से निवेशकों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रुझान तभी देखने में आएगा जब टकराव पूरी तरह समाप्त हो जाए। अभी तो यह आशंका ही बरकरार है कि गतिरोध टूटा भी है या नहीं।

चुप्पी ही उपचार

धर्म-दर्शन

मनमोहन। हर व्यक्ति अपने शब्दों के प्रयोग से अपने संसार का निर्माण करता है। दूसरों से बातचीत में शब्दों का आदान–प्रदान और विचारों में स्वयं के साथ शब्दों का आदान–प्रदान ही उसे जीवन या संसार से मिले अनुभव को जन्म देता है। इसके अलावा हम खुशनुमा शब्दों का इस्तेमाल कर किसी का दिन अच्छा बना सकते हैं या कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर बुरा। एक पुरानी कहावत है, "छड़ी या पत्थर मेरी हड्डियों को तोड़ सकते हैं लेकिन शब्द मुझे किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचा सकता।" यह सच है लेकिन सिर्फ कहने में आसान है करने में नहीं। हम अक्सर शब्दों से चोट खाते हैं और दिखा नहीं पाते। हालांकि, शब्दों की ताकत के बारें में थोड़ी सी जागरुकता भी किसी के संसार में या उसके आस–पास की दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।

संपादकीय

मनोवैज्ञानिकों की जिज्ञासा

मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास कहां से आता है, यह मनोवैज्ञानिकों की जिज्ञासा का विषय रहा है। पिछले दिनों हुए एक शोध में पाया गया कि इसका संबंध हमारी सामाजिक हैसियत से है। संपन्न तबके से आने वालों के भीतर आत्मविश्वास ज्यादा होता है और कमजोर पृष्ठभूमि वाले लोगों के भीतर कम। वर्जिनिया विश्वविद्यालय द्वारा की गई यह स्टडी 'जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल सायकॉलजी' में प्रकाशित हुई है। यह अध्ययन चार चरणों में संपन्न हुआ।

पहले चरण में मेक्सिको के 1,50,949 छोटे कारोबारियों को शामिल किया गया जिन्होंने लोन के लिए आवेदन किए थे। उनसे कई प्रश्नों के उत्तर देने को कहा गया। फिर उनसे पूछा गया कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, यानी कितने उत्तर सही होने की संभावना है? उन व्यापारियों में जो ज्यादा संपन्न थे, वे अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त थे, जबकि कम संपन्न व्यापारियों को लग रहा था कि उन्होंने कई गलतियां की हैं। उत्तरों की जांच में दोनों की हकीकत अलग पाई गई। दूसरे चरण में 433 लोगों के बीच एक ऑनलाइन सर्वे किया गया, जिसमें पूछा गया कि वे अपने और अपने सामाजिक समूह के भविष्य को लेकर कितने आशावादी हैं। जो ज्यादा संपन्न थे, वे ज्यादा आशावादी निकले। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने से और ऊंचे वर्ग में जा सकते हैं।

मुख्य शोधकर्ता पीटर बेल्मी के अनुसार समाज में ऊंची हैसियत रखने वाले व्यक्तियों के भीतर यह भाव रहता है कि उनकी स्थिति हमेशा ज्यादातर लोगों से ऊपर ही रहेगी। उन्हें शुरू से इस तरह से तैयार किया जाता है कि वे औरों से अलग और उनसे बेहतर हैं।

इमीग्रेशन में तरजीह उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनके पास हायर एजुकेशन की डिग्री हो, प्रफेशनल क्वालिफिकेशन हो, अमेरिका में जॉब का ऑफर हो या खुद वहां लोगों को नौकरियां देने की स्थिति में हो, और जो इंग्लिश बोलता हो।

इमीग्रेशन में तरजीह

निहारिका

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने वीजा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रख दिया है, जिसके तहत मेरिट के आधार पर ही विदेशियों को अमेरिका में आने की इजाजत दी जाएगी। अभी तक सिर्फ 12 फीसदी लोगों को स्किल की वजह से ग्रीन कार्ड दिया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत इसे बढ़ाकर 57 फीसदी कर दिया जाएगा।

मौजूदा नियमों के मुताबिक ज्यादातर लोगों को वीजा पारिवारिक संबंधों के आधार पर मिलता है। मसलन, किसी व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य अगर अमेरिका में है तो उसके लिए वीजा मिलना आसान होता था। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। इमीग्रेशन में तरजीह उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनके पास हायर एजुकेशन की डिग्री हो, प्रफेशनल क्वालिफिकेशन हो, अमेरिका में जॉब का ऑफर हो या खुद वहां लोगों को नौकरियां देने की स्थिति में हो, और जो इंग्लिश बोलता हो। इन सारी योग्यताओं के साथ उसे नागरिक शास्त्र का एक टेस्ट भी पास करना होगा।

ट्रंप की दलील है कि वह सस्ती मजदूरी पर काम करने वाले बेकार विदेशियों की भीड़ अमेरिका

में नहीं जमा करना चाहते। वह चाहते हैं कि योग्य विदेशी वहां आएं और अमेरिका के निर्माण में अपना योगदान दें। गौरतलब है कि अमेरिका हर साल तकरीबन 11 लाख ग्रीन कार्ड जारी करता है। इनके जरिये विदेशी नागरिकों को जिंदगी भर अमेरिका में रहकर काम करने की इजाजत मिल जाती है। यह कार्ड जारी होने के पांच साल बाद अगर वे चाहें तो उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता भी खुल जाता है।

बताया जाता है कि ट्रंप की इस नई योजना के पीछे उनके दामाद जैरर्ड कुशनर का दिमाग है। इसके पीछे यह मान्यता काम कर रही है कि अमेरिका में रहने वाले विदेशी अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं जो वहां कुछ करते–धरते नहीं, उलटे अमेरिका की सामाजिक सुरक्षा पर बोझ बन जाते हैं। भारतीयों में ही एक तबके को यह योजना आकर्षक लग रही है। उन्हें लगता है कि नई नीति से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हजारों भारतीय पेशेवरों की मुश्किलें खत्म हो सकती हैं और भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका जाना आसान हो सकता है। लेकिन डर इस बात का है कि क्वॉलिफिकेशन, टेस्ट और तमाम तरह की शर्तें वीजा न देने का बहाना बन जाएंगी। वहां काम कर रहे भारतीयों के परिजनों को वीजा न दिए जाने का प्रभाव उनके कामकाज पर भी पड़ सकता है।

अगर किसी की पत्नी या बुजर्ग मां–बाप उसके साथ रहते हैं तो वह व्यक्ति घर–गृहस्थी, बच्चों के लालन–पालन आदि की तरफ से निश्चिंत होकर अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकता है। नए प्रस्तावों के तहत कोई प्रफेशनल अपने प्रतिभा के बूते अमेरिका चला भी जाए तो वहां उसकी काफी ऊर्जा रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में ही नष्ट हो जाएगी और उसका सर्वोत्तम योगदान अमेरिका को शायद ही मिल पाएगा।

सूडोकु नवताल-5193

सरल

3	9			1	4			2
1	2		6		3		5	
		5		8	7			9
	7			6	9			8
2	1			5			4	6
4			3	2			9	
9			8	4		5		
	6		9		5		2	4
8			1	7			6	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5192 का हल

6	9	2	3	7	4	5	8	1
3	8	5	6	2	1	7	4	9
7	4	1	8	9	5	6	2	3
2	3	9	5	4	6	8	1	7
1	7	4	9	8	3	2	6	5
5	6	8	7	1	2	9	3	4
4	5	7	1	6	8	3	9	2
8	2	3	4	5	9	1	7	6
9	1	6	2	3	7	4	5	8

अपना ब्लॉग

संकट पड़ने पर सरकार का मुंह क्यों देखें

उमेश चतुर्वेदी। तेलंगाना की पशु चिकित्सक प्रियंका रेड्डी की बलात्कार के बाद हुई हत्या से उपजा आक्रोश अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। इन संदर्भों में सोशल मीडिया पर परस्पर विरोधी स्वर न उठते तो ही हैरत होती। ऐसा नहीं कि महिला उत्पीड़न ही इस दौर की सबसे बड़ी समस्या है।

चौबीसो घंटे के मीडिया और सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में पूरा विमर्श किसी एक कुचर्चित घटना के इर्द–गिर्द ही केंद्रित हो जाता है। इससे वैसी घटना के भविष्य में न घटित होने की न तो कोई गारंटी होती है, ना ही दूसरे तरह के अनाचार थम जाते हैं। कड़े कानून भी इन्हें रोकने की गारंटी नहीं देते। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद उपजे विक्षोभ और उसके बाद बने कठोर कानूनों के चलते बार–बार ऐसी घटनाएं नहीं होतीं। जेपी कहते हैं, 'राज्य व्यवस्था को व्यापकतर सामाजिक ढांचे में समायोजित होना होगा और बृहत्तर सामाजिक लक्ष्य में सहायक होना होगा।'